RNI No. MPHIN/2015/64451 डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/1525/2022-2024 IPT डाक द्वारा प्रेषण प्रति शुक्रवार indianplasttimes@gmail.com

DPR No. N-193
www.Indianplasttimes.in

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

■ INDORE ■ 07 FEBRUARY TO 13 FEBRUARY 2024 ■ प्रति बुधवार ■ वर्ष 09 ■ अंक 20 ■ पृष्ठ 8 ■ कीमत 5 रु.

Inside News

अडानी ग्रुप गुजरात में बना रहा दुनिया का सबसे बड़ा तांबा प्लांट
Page 2

हाईवे पर बनेंगे आरामगाह...मिलेगा घर जैसा आराम
Page 3

देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक का प्रॉफिट 35 प्रतिशत गिरा
Page 4

editoria!

राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वप्रथम

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश की सुरक्षा नीति और विदेश नीति स्पष्ट है तथा भारत सभी देशों के साथ मित्रता का आकांक्षी है, पर सीमा और नागरिकों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं हो सकता. उन्होंने यह भी रेखांकित किया है कि पहले विदेश नीति का दबाव सुरक्षा नीति पर रहता था, जिसके कारण आंतरिक सुरक्षा से संबंधित कई समस्याएं पैदा हुईं. भारत की नीतिगत स्पष्टता का सम्मान अन्य देशों ने भी किया है. इसका सबसे बड़ा उदाहरण जी-20 के शिखर सम्मेलन में भारत की अध्यक्षता में संयुक्त घोषणा पर सभी सदस्यों का सहमत होना है. आज दुनिया दो खेमों में विभाजित है तथा अमेरिका तथा रूस एवं चीन के बीच शीत युद्ध चल रहा है. ऐसे वातावरण में घोषणा पर सहमति एक बड़ी उपलब्धि है. रूस-यूक्रेन युद्ध, इस्राइल-हमास संघर्ष, लाल सागर में तनाव जैसे भू-राजनीतिक टकरावों में सभी संबद्ध पक्षों ने भारत की राय को मान दिया है. एक ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मंचों पर ग्लोबल साउथ के देशों का नेतृत्व कर रहा है तथा बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के लिए प्रयासरत है, वहीं चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देश भारत के विरुद्ध आक्रामक रवैया अपनाये हुए हैं. विदेश मंत्री एस जयशंकर पहले कह चुके हैं कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जब तक अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति बहाल नहीं होगी, तब तक भारत और चीन के संबंध सामान्य नहीं हो सकते. चीन ने पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के आंतरिक मामलों पर भी कई बार टिप्पणी की है. तनाव के बावजूद भारत दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों की बैठकों में भाग लेता रहा है. इससे इंगित होता है कि भारत संबंध सुधारने का पक्षधर है. अब यह चीन पर निर्भर करता है कि वह भारत के साथ कैसा संबंध रखना चाहता है. लंबे समय से पाकिस्तान की सरकार और सेना द्वारा वैसे आतंकी गिरोहों और सरगनाओं को पनाह व मदद मुहैया कराया जाता रहा है, जो भारत को अस्थिर करना तथा अलगाववाद को बढ़ावा देना चाहते हैं. ऐसे में पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने का कोई आधार नहीं है. फिर भी अपने पहले कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान से संबंध सुधारने का पूरा प्रयास किया था. कुछ दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने की बात कही थी ताकि उधर से घुसपैठ को रोका जा सके. चीन और पाकिस्तान को छोड़ दें, तो अन्य दक्षिण एशियाई देशों के साथ भारत के संबंध लगातार बेहतर हुए हैं. विदेश और सुरक्षा नीति के सामंजस्य का ही परिणाम है कि जम्मू-कश्मीर, पूर्वोत्तर और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित इलाकों में हिंसा में भारी कमी आयी है.

कीमतों में कमी के लिए करना होगा लंबा इंतजार, तेल कंपनियों के सामने आई ये चुनौती

नई दिल्ली। एजेंसी

देश में पेट्रोल-डीजल की कीमत कम न होने की वजह सामने आई है। वैश्विक बाजारों में कच्चे तेल की कीमत में इजाफा होने से तेल कंपनियों को डीजल बिक्री पर फिर से घाटा होना शुरू हो गया है। मौजूदा समय में सरकारी तेल कंपनियों को डीजल पर प्रति लीटर लगभग तीन रुपये का घाटा हो रहा है जबकि पेट्रोल पर उनके मुनाफे में कमी आई है। तेल उद्योग के अधिकारियों की ओर से जानकारी दी गई। साथ ही बताया कि पेट्रोल पर मुनाफे में कमी आने और डीजल पर घाटा होने से तेल बिक्री करने वाली पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कटौती करने से परहेज कर रही हैं।

22 महीनों से नहीं बदले पेट्रोल-डीजल के दाम

अप्रैल, 2022 से ही पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बदलाव नहीं हुआ है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी), भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) का देश के करीब 90

प्रतिशत ईंधन बाजार पर नियंत्रण है। इन कंपनियों ने कच्चे तेल में घट-बढ़ के बावजूद लंबे समय से पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस (एलपीजी) की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। भारत अपनी तेल जरूरतों को पूरा करने के लिए 85 प्रतिशत आयात पर निर्भर है।

कच्चे तेल की कीमत में उछाल

पिछले साल के अंत में कच्चा तेल नरम हो गया था लेकिन जनवरी के दूसरे पखवाड़े में यह फिर से चढ़ गया। वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल का सूचकांक ब्रेंट क्रूड 78 डॉलर के आसपास चल रहा है। तेल उद्योग के एक अधिकारी ने कहा कि डीजल पर घाटा हो रहा है। हालांकि यह सकारात्मक हो गया था लेकिन अब तेल कंपनियों को लगभग तीन रुपये प्रति लीटर का नुकसान हो रहा है। इसी के साथ पेट्रोल पर मुनाफा मार्जिन भी कम होकर लगभग तीन-चार रुपये प्रति लीटर हो गया है।

पेट्रोलियम कीमतों में बदलाव के बारे में पूछे जाने पर पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 'भारतीय ऊर्जा सप्ताह' के दौरान मीडिया से कहा कि सरकार कीमतें तय नहीं करती है और तेल कंपनियां सभी आर्थिक पहलुओं पर विचार करके अपना निर्णय लेती हैं। इसके साथ ही पुरी ने कहा कि तेल कंपनियां कह रही हैं कि अभी भी बाजार में अस्थिरता है।

हर झटका झेलने के लिए तैयार भारत, 616 अरब डॉलर के पार पहुंचा विदेशी मुद्रा भंडार

नई दिल्ली। एजेंसी

भारत किसी भी झटके को झेलने लिए बिल्कुल तैयार है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में उसकी बढ़ती हैसियत का एक और आंकड़ा आया है। 26 जनवरी को खत्म हुए हफ्ते में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 616 अरब डॉलर को लांघ गया। यह 59.1 करोड़ डॉलर बढ़कर 616.733 अरब डॉलर पर पहुंच गया। इससे एक हफ्ते पहले विदेशी मुद्रा के कुल भंडार में 2.795 अरब डॉलर की भारी गिरावट देखने को मिलती थी। यह लुढ़ककर 616.143 अरब डॉलर रह गया था। किसी भी देश का विदेशी मुद्रा भंडार कई मायनों में अहम होता है। यह देश के आयात बिलों के पेमेंट में सरकार को सहूलियत देता है। जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल घरेलू करंसी में स्टेबिलिटी लाने के लिए किया जा सकता है। यह अर्थव्यवस्था में भरोसा पैदा करता है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार अक्टूबर, 2021 में 645 अरब डॉलर के सर्वकालिक ऊंचे स्तर पर पहुंच गया था। लेकिन, पिछले साल वैश्विक घटनाक्रम के बीच रुपये को संभालने के लिए रिजर्व बैंक को इस भंडार के एक हिस्से का इस्तेमाल करना पड़ा था।

क्या कहती है RBI की रिपोर्ट

विदेशी मुद्रा भंडार पर रिजर्व बैंक के ताजा आंकड़े शुक्रवार को आए। इन आंकड़ों के मुताबिक, 26 जनवरी को समाप्त सप्ताह में मुद्राभंडार का अहम हिस्सा मानी जाने वाली विदेशी मुद्रा आस्तियां (FCA) 28.9 करोड़ डॉलर बढ़कर 546.144 अरब डॉलर हो गईं। फॉरेन करंसी एसेट्स यानी विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों को डॉलर में दर्शाया जाता है। यह विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा घटक होता है। इस पर यूरो, पाउंड और येन जैसी गैर-अमेरिकी मुद्राओं की घट-बढ़ का असर पड़ता है। रिजर्व बैंक के मुताबिक, समीक्षाधीन सप्ताह में गोल्ड रिजर्व यानी स्वर्ण भंडार 26.9 करोड़ डॉलर बढ़कर 47.481 अरब डॉलर हो गया। इसका इस्तेमाल आर्थिक संकट के दौरान देश की अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए किया जा सकता है।

कच्चा तेल 79 डॉलर प्रति बैरल के करीब, पेट्रोल-डीजल की कीमत स्थिर

नई दिल्ली। एजेंसी

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के मूल्य में उतार-चढ़ाव लगातार जारी है। ब्रेंट क्रूड 79 डॉलर प्रति बैरल और डब्ल्यूटीआई क्रूड 74 डॉलर प्रति बैरल के करीब है। हालांकि, तेल एवं गैस विपणन कंपनियों ने बुधवार को पेट्रोल और डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया है।

इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार, दिल्ली में पेट्रोल 96.72 रुपये, डीजल 89.62 रुपये, मुंबई में पेट्रोल 106.31 रुपये, डीजल 94.27 रुपये, कोलकाता में पेट्रोल 106.03 रुपये, डीजल 92.76 रुपये, चेन्नई में पेट्रोल 102.63 रुपये और डीजल 94.24 रुपये प्रति लीटर की दर पर उपलब्ध है।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में हफ्ते के तीसरे दिन शुरुआती कारोबार में ब्रेड क्रूड 0.15 डॉलर यानी 0.19 फीसदी की बढ़त के साथ 78.74 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेंड कर रहा है। वहीं, वेस्ट टेक्सस इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) क्रूड 0.19 डॉलर यानी 0.26 फीसदी की उछाल के साथ 73.50 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर है।

अडानी ग्रुप गुजरात में बना रहा दुनिया का सबसे बड़ा तांबा प्लांट

1.2 अरब डॉलर से होगा तैयार

नई दिल्ली। एजेंसी

अरबपति कारोबारी गौतम अडानी की अगुवाई वाला अडानी ग्रुप दुनिया का सबसे बड़ा तांबा प्लांट बना रहा है। यह प्लांट गुजरात के मुंद्रा में बनाया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक, इस संयंत्र से आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने और ऊर्जा बदलाव में मदद मिलेगी। मामले की जानकारी रखने वाले दो सूत्रों ने बताया कि 1.2 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश से तैयार हो रहा यह संयंत्र मार्च के अंत तक पहले चरण का परिचालन शुरू कर देगा। उन्होंने बताया कि संयंत्र मार्च, 2029 तक पूर्ण पैमाने पर 10 लाख टन क्षमता के साथ काम शुरू करेगा।

भारत तेजी से बढ़ा रहा उत्पादन

चीन और अन्य देशों की तरह भारत भी तांबे का उत्पादन तेजी से बढ़ा रहा है, जो जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण धातु है। ऊर्जा बदलाव के लिए महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों जैसे इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी), चार्जिंग अवसंरचना, सौर फोटोवोल्टिक (पीवी), पवन ऊर्जा और बैटरी सभी में तांबे की जरूरत होती है।

अडाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (एईएल) की सब्सिडियरी कंपनी कच्छ कॉपर लिमिटेड (केसीएल) दो चरण में 10 लाख टन सालाना क्षमता वाली तांबा रिफाइनरी परियोजना स्थापित कर रही है। पहले चरण में पांच लाख टन प्रति वर्ष की क्षमता शुरू की जाएगी। इसके लिए केसीएल ने जून, 2022 में फाइनेंसिंग हासिल किया था।

देश में इतनी है तांबे की खपत

सूत्रों में से एक ने कहा, ''अडानी समूह संसाधन कारोबार, लॉजिस्टिक, नवीकरणीय ऊर्जा और बुनियादी ढांचे में अपनी मजबूत स्थिति का लाभ उठाकर तांबे के कारोबार में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनना चाहता है।'' उन्होंने कहा कि भारत में प्रति व्यक्ति तांबे की खपत लगभग 600 ग्राम है, जबकि वैश्विक औसत 3.2 किलोग्राम है।

एफएमसीजी की बड़ी कंपनियों को क्यों घटाने पड़ रहे दाम?

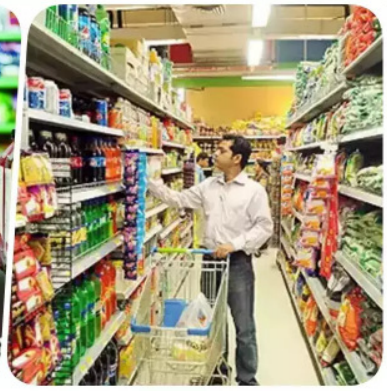

नई दिल्ली। एजेंसी

रोजमर्रा इस्तेमाल के सामान बनाने वाली एफएमसीजी (इश्ण्उ) की बड़ी कंपनियों को दाम घटाने पड़ रहे हैं। इन कंपनियों को क्षेत्रीय और छोटे ब्रांड्स से कड़ी टक्कर मिल रही है। ये छोटी कंपनियां और ब्रांड्स कम कीमत पर सामान बेच रहे हैं। इससे हिंदुस्तान यूनिलीवर, पारले प्रोडक्ट्स, मैरिको और अडानी विल्मर जैसी कंपनियों को अब अपने प्रोडक्ट्स की कीमतों को कम करना पड़ रहा है। अब इन बड़ी कंपनियों को मजबूरी में सामान के दाम कम करने पड़ रहे हैं। पिछले 6 से 9 महीनों में इन बड़ी एफएमसीजी कंपनियों ने जहां पर जरूरी था वहां पर दाम कम करे हैं या फिर पैक का वजन बढ़ाया है। इसी के साथ ही इन कंपनियों ने विज्ञापन और प्रचार पर ज्यादा रुपये खर्च करने शुरू कर दिए हैं। अब इन कंपनियों को अपनी बिक्री में सुधार दिख रहा है। कंपनियों को उम्मीद है कि आने वाले समय में मांग बढ़ने से और ज्यादा फायदा होगा।

छोटी कंपनियां दे रहीं कड़ी टक्कर

इन बड़ी एफएमसीजी कंपनियों को छोटी कंपनियां कड़ी टक्कर दे रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनियों ने पिछले सितंबर महीने से छोटे पैक का वजन बढ़ाना शुरू कर दिया है। इससे कंपनियों को पिछली तिमाही में छोटी कंपनियों के मुकाबले हिस्सेदारी में इजाफा देखने को मिला है। कंपनियों को उम्मीद है कि कीमत में सुधार और पैक का वजन बढ़ाने की वजह से वह क्षेत्रीय कंपनियों से मुकाबला कर सकेंगी। कंपनियों की योजना अपना निवेश जारी रखने की है, जिससे बाजार की मौजूदा स्थिति में सुधार होने पर उन्हें इसका फायदा मिलेगा।

विज्ञापन पर ज्यादा खर्च

कंपनियां अपने पैक का वजन बढ़ाने के साथ विज्ञापन और प्रचार-प्रसार पर भी ज्यादा रुपये खर्च कर रही हैं। इसका असर इन कंपनियों के मुनाफे पर पड़ा है। कंपनियों का मुनाफा घटा है, लेकिन कंपनियों को उम्मीद है कि आने वाले समय में बाजार में सुधार होने पर उन्हें इसका फायदा जरूर मिलेगा। इससे आने वाले दिनों में उनका मुनाफा काफी बढ़ जाएगा।

रेलवे को मिलने वाली है स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन

नई दिल्ली। एजेंसी

देश में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन फरवरी 2019 में नई दिल्ली से वाराणसी के बीच शुरू की गई थी। उसके बाद से अब तक देश में चेयर कार सुविधा वाली कुल 34 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चलाई जा चुकी है। सरकार अब इस सेमी हाई-स्पीड ट्रेन का स्लीपर वर्जन निकालने की तैयारी में है। इसे राजधानी एक्सप्रेस के रूट पर चलाया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो इसका प्रोटोटाइप तैयार हो चुका है और अप्रैल में ट्रायल रन शुरू हो सकता है। सबसे पहले इसे दिल्ली-मुंबई और दिल्ली-हावड़ा रूट पर चलाया जा सकता है। इनमें एसी और नॉन-एसी कोच होंगे।

चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (ICF) के जनरल मैनेजर बी जी माल्या ने हाल में कहा था कि इस वित्तीय वर्ष के दौरान वंदे का स्लीपर वर्जन लॉन्च कर दिया जाएगा। स्लीपर वंदे भारत को एक कंसोर्टियम बना रहा है। इसमें रेल विकास निगम लिमिटेड और रूस का टीएमएच ग्रुप शामिल है। इस कंसोर्टियम ने 200 में से 120 स्लीपर वंदे भारत चलाने के लिए सबसे कम बोली लगाई थी। बाकी 80 ट्रेनें की सप्लाई टीटागढ़ वैगन्स और बीएचईएल का कंसोर्टियम सप्लाई करेगा। आरवीएनएल के जीएम (मैकेनिकल) आलोक कुमार मिश्रा ने पिछले साल अगस्त में कहा था कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की रफ्तार 160 किमी प्रति घंटे होगी। इसमें 16 कोच होंगे जिनमें 11 एसी3, चार एसी2 और एक एसी1 कोच होगा। उनका कहना था कि कोच की संख्या 20 या 24 की जा सकती है।

तीन नए कॉरिडोर

साथ ही वंदे मेट्रो को भी बनाया जा रहा है। 12 कोच की इस ट्रेन को छोटे रूट पर चलाया जाएगा। हाल में पेश अंतरिम बजट में तीन नए रेल कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव है। असल में ये केवल तीन रेल कॉरिडोर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इन तीनों से 434 प्रोजेक्ट जुड़े हुए हैं। दावा किया जा रहा है कि इससे देश में रेलवे का कायाकल्प हो जाएगा। 6-8 साल में पूरे होने वाले इन तीनों कॉरिडोर की लंबाई 40 हजार किलोमीटर होगी। तीनों कॉरिडोर के लिए 40 हजार किलोमीटर लंबे रेल ट्रैक बिछाने के लिए आरंभिक लागत 11 लाख करोड़ रुपये आने का अनुमान है। उम्मीद जताई जा रही है कि 2030-31 तक देश में रेल टिकट बुक कराने वालों के लिए वेटिंग लिस्ट का झंझट खत्म हो सकेगा।

हाईवे पर बनेंगे आरामगाह...मिलेगा घर जैसा आराम

हजारो ट्रक ड्राइवर होंगे लाभन्वित

कानपुर। एजेंसी

हिट एंड रन के नए प्रस्तावित कानून के बाद सुर्खियों में आए ट्रक ड्राइवरों के आराम के बारे में भी सरकार ने सोचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण में ट्रक ड्राइवरों के काम करने के घंटे और उनके दिन रात की मेहनत का जिक्र किया है। कहा कि जो ट्रक और टैक्सी ड्राइवर हैं। वह हमारी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का अभिन्न अंग हैं। अक्सर ये ड्राइवर घंटों ट्रक चलाते हैं इनके पास आराम का समय नहीं होता। इनके लिए केंद्र सरकार सभी नेशनल हाईवे पर ड्राइवरों के लिए आधुनिक भवनों का निर्माण करने जा रहा है। भाजपा के अधिकारिक एक्स अकाउंट पर प्रधानमंत्री की सोच को अमल में लाने की बात कही गई है।

इस योजना के अमल में आने पर कानपुर संभागीय परिवहन विभाग में दर्ज 88 हजार ट्रक ड्राइवरों को लाभ मिल सकेगा। इस संदर्भ में आरटीओ राजेश सिंह ने बताया कि सरकार की यह बड़ी सार्थक पहल है। इस योजना के लागू होने के बाद ट्रक ड्राइवरों को सफर के दौरान आराम और अच्छे भोजन के लिए भटकना नहीं पडेगा।

सहूलियत के निकाले जा रहे हैं सियासी मायने

पोर्टल पर कानपुर जिले में 88 हजार भारी वाहनों के ड्राइवर दर्ज हैं। लंबी दूरी पर चलने वाले ट्रक ड्राइवर कई दिनों तक सफर में रहते हैं। ये ड्राइवर अक्सर अपनी गाड़ी के केबिन में ही सो जाते हैं। नेशनल हाईवे पर ड्राइवरों को मिलने जा रही इस सुविधा के बाद होने वाले हादसों पर भी काफी हद तक काबू पाया जा सकेगा। लोकसभा चुनावों से पहले ट्रांसपोर्ट कारोबार से जुड़े ड्राइवर वर्ग को दिए जाने वाली सहूलियत के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं।

OECD ने भारत की वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 6.2 प्रतिशत किया

महंगाई में कमी की उम्मीद

एजेंसी

आर्थिक सहयोग एवं विकास परिषद (OECD) ने सोमवार को जारी अपने ताजा अंतरिम आर्थिक परिदृश्य में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 6.2 प्रतिशत कर दिया है। इसके पहले ध्ंिंऊ नवंबर के परिदृश्य में 6.1 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया था। परिदृश्य में कहा गया है, 'तंग वित्तीय स्थिति के बावजूद उभरते बाजारों की अर्थव्यवस्थाएं सामान्यतया मजबूत वृद्धि जारी रखेंगी। भारत सहित तमाम देशों में व्यापक आर्थिक नीति के ढांचे में सुधार नजर आ रहा है और रोजगार सृजन हो रहा है।'

वित्त वर्ष 26 के लिए ध्ंिंऊ ने भारत के लिए वृद्धि अनुमान 6.5 प्रतिशत बरकरार रखा है। इसमें कहा गया है कि प्रमुख गतिविधियों के संकेतकों से सामान्यतया हाल की वृद्धि जारी रहने के संकेत मिल रहे हैं। कारोबारी सर्वे में विनिर्माण क्षेत्र की तुलना में सेवा क्षेत्र में मजबूत गतिविधियों के संकेत मिल रहे हैं। परिदृश्य में कहा गया है, 'अगर सभी देशों की स्थिति देखें तो निकट अवधि के हिसाब से भारत में मजबूती के संकेत मिल रहे हैं। वहीं यूरोप में तुलनात्मक रूप से कमजोर स्थिति रहेगी और अन्य बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में निकट अवधि की वृद्धि थोड़ी सुस्त रहेगी।' महंगाई दर को लेकर रिपोर्ट में कहा गया है कि उभरते बाजार की अर्थव्यवस्थाओं में महंगाई दर विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में सामान्यतया अधिक बनी रहोगी, जबकि 2024-25 में धीरे धीरे इसमें कमी आएगी। इन तमाम अर्थव्यवस्थाओं में सख्त मौद्रिक नीति और ऊर्जा व खाद्य कीमतें महंगाई दर की मुख्य चालक रहेंगी।

PMI: भारत में सेवा क्षेत्र की गतिविधियां जनवरी में छह महीने के उच्चतम स्तर पर, पीएमआई 61.8 पर पहुंचा

नई दिल्ली। एजेंसी

भारत में सेवा क्षेत्र की गतिविधियां अनुकूल आर्थिक परिस्थितियों और सकारात्मक मांग के दम पर जनवरी में छह महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। एक मासिक सर्वेक्षण में यह जानकारी दी गई है। इस दौरान मौसमी रूप से समायोजित एचएसबीसी इंडिया भारत सेवा पीएमआई कारोबारी गतिविधि सूचकांक जनवरी में 61.8 पुहंच गया। यह दिसंबर में 59 पर था। खरीद प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) की भाषा में 50 से ऊपर के अंक का मतलब गतिविधियों में विस्तार से और 50 से कम अंक का आशय संकुचन से होता है। सर्वेक्षण सेवा क्षेत्र की करीब 400 कंपनियों को भेजे गए प्रश्नावली के जवाबों पर आधारित है। एचएसबीसी के अर्थशास्त्री इनेस लैम ने कहा, '' भारत की सेवा पीएमआई जनवरी में छह महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गईं। नए व्यवसाय का विस्तार तेज गति से हुआ और भविष्य की गतिविधि के लिए प्रबंधकों की उम्मीदें मजबूत बनी हैं। कारोबारी गतिविधि सूचकांक में तेजी आई, जिससे संकेत मिलता है कि भारत का सेवा निर्यात मजबूत बना हुआ है।'' नई निर्यात बिक्री तीन महीनों में सबसे तेज़ गति से बढ़ी। कंपनियों ने अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चीन, यूरोप, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका सहित दुनिया भर में ग्राहकों से लाभ का संकेत दिया। इस बीच, एचएसबीसी इंडिया कंपोजिट पीएमआई आउटपुट इंडेक्स 58.5 से बढ़कर 61.2 हो गया।

UPI लेनदेन हुआ बंद! यूजर्स में मचा हड़कंप, जानें वजह?

एजेंसी

यूपीआई ऐप जैसे फोनपे, गूगल पे, BHIM से ऑनलाइन लेनदेन नहीं हो रहा है, इसे लेकर यूजर्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शिकायत कर रहे हैं। यूजर्स की शिकायत है कि वो यूपीआई पेमेंट सर्विस का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। पेटीएम पेमेंट बैंक पर रोक लग गई थी। UPI इनेबल्ड ऐप जैसे फोनपे, गूगल पे, BHIM से ऑनलाइन लेनदेन नहीं हो पा रहा है, जिसे लेकर यूपीआई यूजर्स काफी परेशान हैं। इसे लेकर यूजर्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शिकायत कर रहे हैं। यूजर्स की शिकायत है कि वो यूपीआई पेमेंट सर्विस का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। इससे पहले पेटीएम पेमेंट बैंक पर रोक लगा दी गई थी। ऐसे में ऑनलाइन पेमेंट के लेकर यूजर्स के बीच डर बैठ गया है।

क्या है मामला?

रिपोर्ट की मानें, तो कई बैंकिंग सर्वर डाउन हो गए हैं, जिसकी वजह से यूपीआई समेत अन्य बैंकिंग सर्विस कुछ वक्त के लिए ठप हो गई थीं। जिन बैंकों के सर्वर डाउन हुए थे, उसमें एचडीएफसी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोटक महिंद्रा बैंक शामिल हैं, क्योंकि बैंकिंग सर्विल ठप हुए थे, ऐसे में ऑनलाइन पेमेंट सर्विस यूपीआई पर भी असर देखने को मिल रहा है।

पैसे ट्रांसफर करने में आ रही दिक्कत

Downdetector वेबसाइट की ओर से यूपीआई सर्विस के ठप होने की सूचना को कंफर्म किया गया है। रिपोर्ट की मानें, तो कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक यूजर्स को यूपीआई सर्विस ठप होने से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसकी वजह से उन्हें पैसों के लेनदेन में इश्यू आ रहा है।

बाजार में आते ही छा गई सरकार की 'भारत दाल'

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

दाल की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगने के लिए सरकार ने पिछले साल अक्टूबर में भारत दाल ब्रांड के तहत चने की दाल बेचना शुरू किया था। इसके एक किलो के पैक की कीमत 60 रुपये रखी गई थी और 30 किलो का बैग 55 रुपये किलो के भाव पर उपलब्ध है। अभी इसे नैफेड, एनसीसीएफ, केंद्रीय भंडार और सफल के जरिए बेचा जा रहा है। साथ ही यह कई ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर भी उपलब्ध है। सरकार का दावा है कि लॉन्च के चार महीने के भीतर ही भारत ब्रांड की चना दाल ने 25% मार्केट कब्जा लिया है। इसकी वजह यह है कि यह मार्केट में मौजूदा दूसरे ब्रांड की तुलना में सस्ती है। दूसरे ब्रांड्स के चना दाल की कीमत 80 रुपये के आसपास है जबकि भारत चना दाल 60 रुपये किलो मिल रही है। दाल की कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार चना, तुअर, उड़द, मूंग और मसूर की दाल का बफर स्टॉक रखती है। बाजार में कीमतों को रेगुलेट करने के लिए इस स्टॉक को रिलीज किया जाता है। सरकार ने 31 मार्च तक तुअर और उड़द की दाल पर इम्पोर्ट ड्यूटी खत्म कर दी है जबकि मसूर की दाल पर इसे जीरो कर दिया गया है। साथ ही तुअर और उड़द पर स्टॉक लिमिट लगा दी गई है ताकि इसकी कालाबाजारी न हो पाए। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में सचिव रोहित कुमार सिंह ने कहा कि ग्राहकों के बीच भारत ब्रांड की चना दाल की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है। चार महीने में ही इसने एक चौथाई मार्केट कब्जा लिया है।

कागज की जगह प्लास्टिक के नोट लाने की हो रही है प्लानिंग...

वित्त मंत्रालय ने दिया यह जवाब

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने मंगलवार को कहा कि सरकार ने प्लास्टिक नोट लाने का कोई निर्णय नहीं लिया है। उन्होंने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि भारतीय बैंक नोटों के स्थायित्व और नकली नोटों को रोकने की कोशिश निरंतर जारी रहेगी। आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार, उन्होंने कहा कि 2022-23 के लिए सुरक्षा मुद्रण पर कुल खर्च 4682.80 करोड़ रुपये था। इसमें प्लास्टिक नोटों की छपाई पर कोई लागत नहीं आई है। मंत्री ने कहा कि सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 25 के संदर्भ में प्लास्टिक नोट पेश करने का कोई निर्णय नहीं लिया है। भारतीय बैंक नोटों की स्थायित्व और नकली नोटों को बाजार में आने से रोकने को लेकर सरकार निरंतर प्रयासरत है। एक अन्य सवाल के जवाब में चौधरी ने कहा कि क्रिप्टो एसेट सहित किसी भी प्रकार की संपत्ति का उपयोग करके अवैध वस्तुओं का व्यापार करना एक अपराध है और मौजूदा दंडात्मक प्रावधानों के अनुसार इससे निपटा जाता है। उन्होंने कहा कि पीएमएलए के तहत एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल)/काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म (सीएफटी) प्रावधान क्रिप्टो एसेट सहित मनी लॉन्ड्रिंग को और अधिक दंडित करते हैं।मंत्री ने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा 7 मार्च 2023 को जारी नोटिफिकेशन के जरिए वीडीए की स्पष्ट रूप से रोकथाम और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 (पीएमएलए) के दायरे में ला दिया है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी पीएमएलए के प्रावधानों के तहत संदिग्ध वीडीए लेनदेन से संबंधित मामलों को संभालता है।इसमें विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) और भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 (एफईओए) शामिल है। उन्होंने कहा कि यह देखते हुए कि सरकार को पता है कि देश में क्रिप्टो एसेट लेनदेन हो रहे है। उन्होंने कहा, इसलिए इन लेनदेन को वित्त अधिनियम 2022 के माध्यम से एक व्यापक टैक्ससेशन व्यवस्था में लाया गया है। क्रिप्टो एसेट के संपर्क में आने वाली कंपनियों को खुलासा करना आवश्यक है कि कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची ष्ष्ष में लाए गए संशोधन के अनुसार, 24 मार्च 2021 को जारी अधिसूचना जो 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी है उसके वित्तीय विवरणों में क्रिप्टो एसेट की हिस्सेदारी है बताना जरूरी है।

दाल, राजमा, मटर समेत खाने-पीने की कई चीजों पर भी पड़ रही है महंगाई की मार

नई दिल्ली। एजेंसी

इस्राइल-हमास युद्ध के बाद लाल सागर में माल ढोने वाले जहाजों पर हमले के खतरे से अब भारत का व्यापार प्रभावित हो रहा है। स्थिति यह है कि भारत से चावल का निर्यात न होने से चावल के दामों में गिरावट आई है, जबकि दाल समेत अन्य चीजों का आयात न होने से लोगों पर महंगाई की मार पड़ने की आशंका बनी हुई है। व्यापारियों का दावा है कि अगर इस समस्या से निजात नहीं मिली तो आने वाले दिनों में कई सामानों के रेट में उछाल आ सकता है।

सामानों की सप्लाई प्रभावित

एग्री फार्मर एंड ट्रेड असोसिएशन के प्रेसिडेंट सुनील बलदेवा ने बताया कि बीते कुछ दिनों से लाल सागर के जरिए सामानों की सप्लाई प्रभावित हुई है। क्योंकि लाल सागर के जरिए जहाजों पर हमले का खतरा है। इससे शिपिंग कंपनियों ने प्रति टन सामानों की ढुलाई में 30 से 50 डॉलर की वृद्धि कर दी है, जिससे व्यापारी परेशान हैं।

कई कमोडिटी की सप्लाई ठप

बाजार में इस समय कई सामानों की सप्लाई लगभग ठप हो चुकी है। सुनील के मुताबिक, अफ्रीका से अरहर की दाल की सप्लाई भारत में होती है, लेकिन सप्लाई चेन प्रभावित होने से बीते कुछ दिनों में अरहर दाल की कीमत में बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा, चावल, सफेद मटर से लेकर कई चीजों की सप्लाई प्रभावित है। साथ ही कनाडा से आने वाले सनफ्लावर और पीले सरसों के तेल की सप्लाई पर भी असर पड़ा है।

चावल हो गया सस्ता

इस युद्ध की वजह से भारत से चावलों का निर्यात नहीं हो पा रहा है। इससे चावल के दाम भरभरा कर गिर गए हैं। नया बाजार के चावल कारोबारी सचिन शर्मा ने बताया कि विदेशों में चावल की सप्लाई भारत से होती है, लेकिन लाल सागर से चावल की होने वाली सप्लाई ठप होने से बीते दस दिनों में बासमती के चावल में प्रति किलो 10 रुपये तक की गिरावट आई है। साथ ही दूसरे देशों से चावल का ऑर्डर लेने वाले व्यापारी भी सप्लाई न देने से परेशान हैं।

शिपिंग कंपनियों ने बढ़ाया किराया

कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स असोसिएशन के दिल्ली अध्यक्ष विपिन आहूजा ने बताया कि शिपिंग कंपनियों ने किराया काफी बढ़ा दिया है, जिससे लाल सागर के जरिए खाने के सामान से लेकर रॉ मटीरियल की सप्लाई प्रभावित हो गई है। इसकी वजह से कुछ चीजों की कीमत में बढ़ोतरी होने की आशंका है। साथ ही कई व्यापारी इस लिए परेशान हैं। सरकार को इस पर कोई रास्ता निकालने की जरूरत है।

भारत आज विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था

भारत ऊर्जा सप्ताह-2024 के शुभारंभ पर बोले पीएम

पणजी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मंगलवार गोवा के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत ऊर्जा सप्ताह-2024 का उद्घाटन करते हुए कहा, ' इस वित्त वर्ष के पहले छह महीनों में भारत की जीडीपी दर 7.5 फीसदी से अधिक हो गई है। भारत आज विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। उन्होंने कहा, 'इंडिया एनर्जी वीक के इस दूसरे संस्करण में आप सभी का अभिनंदन करता हूं। हमारे लिए ये बहुत खुशी की बात है कि इंडिया एनर्जी वीक का आयोजन हमेशा एनर्जी से भरे रहने वाले गोवा में हो रहा है।' प्रधानमंत्री मोदी ने इससे पहले दक्षिण गोवा के बेतुल में ओएनजीसी सी सर्वाइवल सेंटर का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'गोवा अपने आतिथ्य भाव के लिए जाना जाता है। गोवा आज विकास के नए प्रतिमानों को छू रहा है। आज जब हम गोवा में पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता की बात करने के लिए एकजुट हुए हैं। टिकाऊ भविष्य के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसके लिए गोवा परफेक्ट डेस्टिनेशन है।' इससे पहले केंद्रीयमंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, ' प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए विकास केंद्र और वैश्विक ऊर्जा के लिए मांग केंद्र बन रहा है। इस स्थिति को दर्शाते हुए, केवल दो वर्षों में एनर्जी इंडिया एनर्जी वीक वैश्विक ऊर्जा कैलेंडर पर एक प्रमुख तारीख बन गया है। इस वर्ष हमारे पास 900 प्रदर्शक हैं। यह पिछले वर्ष की तुलना में 30 प्रतिशत अधिक है।

देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक का प्रॉफिट 35 प्रतिशत गिरा

नई दिल्ली। एजेंसी

देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई (SBI) ने आज दिसंबर तिमाही के नतीजे घोषित कर दिए। बैंक का स्टैंडअलोन प्रॉफिट अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में 35 परसेंट की गिरावट के साथ 9,164 करोड़ रुपये रहा। पिछले साल समान तिमाही में बैंक को 14,205.34 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ था। बैंक ने कहा कि 7,100 करोड़ रुपये के वन-टाइम एक्सेप्शनल आइटम की अकाउंटिंग के कारण उसका प्रॉफिट गिरा है। दिसंबर तिमाही में बैंक की इंटरेस्ट इनकम 105,733.78 करोड़ रुपये रही जो पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 22ज्ञ अधिक है। पिछले साल दिसंबर तिमाही में बैंक को ब्याज से 86,616.04 करोड़ रुपये की इनकम हुई थी। दिसंबर तिमाही में बैंक ने 66,918 करोड़ रुपये का ब्याज चुकाया। इस तरह बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम (ञ्ष्ष) 38,816 करोड़ रुपये रही। यह पिछले साल के मुकाबले 4.59ज्ञ अधिक है। दिसंबर तिमाही में बैंक का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 20,336 करोड़ रुपये रहा। बैंक ने शेयर मार्केट को दी गई जानकारी में कहा कि फाइनेंशियल ईयर 2024 के पहले नौ महीनों में स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट 20.40ज्ञ बढ़कर 40,378 करोड़ रुपये रहा। पिछले साल समान अवधि में यह 33,538 करोड़ रुपये रहा था। एसबीआई ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि दिसंबर 2023 को समाप्त तिमाही में उसकी कुल आमदनी बढ़कर 1,18,193 करोड़ रुपये रही, जो बीते वित्त वर्ष की समान तिमाही में 98,084 करोड़ थी। बैंक की ब्याज आय समीक्षाधीन तिमाही में बढ़कर 1,06,734 करोड़ रुपये हो गई, जो बीते वित्त वर्ष की समान तिमाही में 86,616 करोड़ रुपये थी। दिसंबर, 2023 के अंत तक बैंक की सकल गैर-निष्पादित संपत्ति (एनपीए) घटकर सकल ऋण का 2.42 प्रतिशत हो गई, जो एक साल पहले 3.14 प्रतिशत थी। इसी तरह, तीसरी तिमाही के अंत में शुद्ध एनपीए भी घटकर 0.64 प्रतिशत हो गया जो पिछले साल 0.77 प्रतिशत था।

ग्रुप का प्रॉफिट भी गिरा

एकीकृत आधार पर एसबीआई समूह का शुद्ध लाभ दिसंबर, 2023 तिमाही में 29 प्रतिशत गिरकर 11,064 करोड़ रुपये रह गया, जो बीते वित्त वर्ष की समान तिमाही में 15,477 करोड़ रुपये था। हालांकि, कुल आमदनी समीक्षाधीन तिमाही में बढ़कर 1,53,072 करोड़ रुपये हो गई, जो बीते वित्त वर्ष की समान तिमाही में 1,27,219 करोड़ रुपये थी। दिसंबर, 2023 तिमाही में बैंक ने एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड में एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड (एसबीआईसीएपीएस) की पूरी 20 प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण कर लिया। इसके साथ ही एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड में बैंक की हिस्सेदारी 60 प्रतिशत से बढ़कर 80 प्रतिशत हो गई। यह सौदा 229.52 करोड़ रुपये में हुआ।

कतर से भारत की 78 अरब डॉलर की वो डील, जिसकी हो रही है चर्चा

भारत और क़तर के बीच मंगलवार को एक अहम समझौता हुआ
अगले 20 सालों के लिए 78 अरब डॉलर की डील
भारत क़तर से साल 2048 तक खरीदेगा लिक्विफ़ाइड नैचुरल गैस (एलएनजी)

नई दिल्ली। एजेंसी

भारत की सबसे बड़ी एलएनजी आयात करने वाली कंपनी पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड (पीएलएल) ने क़तर की सरकारी कंपनी क़तर एनर्जी के साथ ये समझौता किया है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह पुरी और क़तर एनर्जी के सीईओ साद अल-काबी ने गोवा में चल रहे इंडिया एनर्जी वीक 2024 के पहले दिन मंगलवार को ये समझौता किया गया।

इस समझौते को काफ़ी महत्वपूर्ण इस लिहाज़ से भी बताया जा रहा है क्योंकि इसे वर्तमान समझौते से भी काफ़ी कम क़ीमत पर किया गया है। पेट्रोनेट एलएनजी ने अपने बयान में बताया है कि गैस के आयात को लेकर दोनों देशों के बीच 31 जुलाई 1999 को समझौता हुआ था जो 2028 तक के लिए था। अब ये सौदा 20 सालों के लिए हुआ है जो 2028 से शुरू होगा। गैस कुल कितनी क़ीमत पर खरीदी जाएगी इसको लेकर कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि इसकी वर्तमान सौदे से कम क़ीमत होगी।

अंग्रेज़ी अखबार 'द इंडियन एक्सप्रेस' के मुताबिक़, इस नए सौदे से अगले 20 सालों के दौरान तक़रीबन 6 अरब डॉलर बचाए जा सकेंगे। पेट्रोनेट हर साल दो समझौतों के तहत क़तर से 85 लाख टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) एलएनजी आयात करता है। दोनों देशों के बीच पहला समझौता 25 साल पहले हुआ था जो 2028 तक वैध था। इसी को 20 साल और बढ़ाकर 2048 तक कर दिया गया है. वहीं एक एमटीपीए के लिए 2015 में दूसरा सौदा हुआ था। समाचार एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि इस समझौते पर अलग से बातचीत की जाएगी।

भारत और क़तर के बीच रिश्ते काफ़ी बेहतर रहे हैं लेकिन बीते कुछ महीनों में दोनों पक्षों के बीच रिश्ते उतार-चढ़ाव भरे रहे हैं। क़तर दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी का निर्यातक रहा है लेकिन हाल ही में अमेरिका ने उसे पीछे छोड़ दिया है। क़तर सालाना 77 एमटीपीए गैस निकालता है, जिसे 2027 तक वो 126 एमटीपीए करना चाहता है ताकि एशिया और यूरोप में अपनी पकड़ मज़बूत कर सके, जहाँ अमेरिका घुसना चाह रहा है।

बीते साल अक्तूबर में क़तर की एक कोर्ट ने नौसेना के आठ पूर्व अधिकारियों को इसराइल के लिए जासूसी करने के आरोप में मौत की सज़ा सुनाई थी. दिसंबर के अंत में मौत की सज़ा को घटा दिया गया था। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश है और वो साल 2070 तक नेट ज़ीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य लेकर चल रहा है, जिसमें प्राकृतिक गैस की अहम भूमिका है। इसी कोशिश के तहत भारत सरकार देश में प्राकृतिक गैस के इस्तेमाल के शेयर को 6.3 फ़ीसदी से बढ़ाकर 2030 तक 15 फ़ीसदी करना चाहती है।

पेट्रोनेट के सीईओ अक्षय कुमार सिंह कहते हैं कि पेट्रोनेट और क़तर एनर्जी के बीच मौजूदा दीर्घकालिक समझौता भारत के एलएनजी आयात का तक़रीबन 35 फ़ीसदी है और ये राष्ट्रीय महत्व का समझौता है। उन्होंने कहा कि ये समझौता ऊर्जा सुरक्षा मुहैया कराएगा और साथ ही स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित कराएगा और भारत को अधिक आर्थिक विकास की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेगा।

कितनी गैस आयात करता है भारत

क़तर के अलावा भारतीय कंपनियों का एलएनजी के लिए ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के साथ क़रार है लेकिन भारत अपने इस्तेमाल की आधे से अधिक एलएनजी केवल क़तर से ही आयात करता है। भारत के आधिकारिक व्यापार आँकड़ों के मुताबिक़, भारत ने 2022-23 में 19.85 मिलियन टन एलएनजी आयात की थी, जिसमें से तक़रीबन 54 फ़ीसदी 10.74 मिलियन टन क़तर से आई थी।

इसी वित्त वर्ष में क़तर से भारत ने कुल 16.81 अरब डॉलर का आयात किया था, जिसमें से एलएनजी का आयात ही 8.32 अरब डॉलर था जो कि कुल आयात का 49.5 फ़ीसदी था। डीज़ल और पेट्रोल की तुलना में प्राकृतिक गैस को अधिक स्वच्छ विकल्प माना जाता है जो कि कच्चे तेल से आमतौर पर सस्ता होता है।

कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के लिए भारत आयात पर निर्भर है और वो तक़रीबन 85 फ़ीसदी कच्चा तेल आयात करता है. वहीं प्राकृतिक गैस को देश की ऊर्जा ज़रूरतों में बदलाव के लिए इसे बेहद अहम और मुफ़ीद माना जाता है।

क़तर से कैसे आएगी गैस?

भारत और क़तर के बीच एलएनजी को लेकर ये सौदा एक्स शिप बेसिस (डीईएस) पर हुआ है जो जहाज़ के ज़रिए बंदरगाह पर पहुंचेगी। 1999 में हुआ समझौता फ्री ऑन बोर्ड (एफ़ओबी) के आधार पर हुआ था जबकि 2028 से शुरू हो रहा सौदा डीईएस के आधार पर है। ये कहा जा रहा है कि डीईएस के तहत सौदा होने से इसकी लागत कम पड़ रही है क्योंकि एफ़ओबी में गैस खरीदने वाला जहाज़ का इंतज़ाम करता है जबकि डीईएस में इसकी ज़िम्मेदारी बेचने वाले पर होती है। गैस आयात करने वाली भारतीय कंपनी पीएलएल ओएनजीसी, इंडिया ऑयल, गेल और भारत पेट्रोलियम का संयुक्त उपक्रम है।

गुजरात के दहेज में पीएलएल का टर्मिनल है जहां पर जहाज़ से गैस आती है और फिर उसको अलग-अलग पेट्रोलियम कंपनियों में बांटा जाता है। पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड (पीएलएल) का कहना है कि क़तर एनर्जी के साथ हुए समझौते से ये सुनिश्चित होगा कि अधिक खपत वाले सेक्टर्स जैसे कि उर्वरक, सिटी गैस डिस्ट्रिब्यूशन, रिफ़ाइनरियों और पावर जनरेशन को लगातार गैस मिलती रहे।

क़तर के ऊर्जा मंत्री और क़तर एनर्जी के सीईओ साद अल-काबी ने मंगलवार को गोवा में इंडिया एनर्जी वीक समारोह से इतर कहा कि वो भारत में अपने मार्केट के लिए मौजूद हैं और उम्मीद है कि इससे अर्थव्यवस्था में विस्तार होगा जो ऊर्जा क्षेत्र की ज़रूरत भी है।

भारत-क़तर के संबंधों में उतार-चढ़ाव

भारत और क़तर के मित्रतापूर्ण संबंध रहे हैं. लेकिन इस रिश्ते में पहली चुनौती जून 2022 में आई, जब बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने एक टीवी शो में पैगंबर मोहम्मद के बारे में विवादित टिप्पणी की थी। उस दौरान क़तर पहला देश था, जिसने भारत से 'सार्वजनिक माफ़ी' की मांग की। क़तर ने भारतीय राजदूत को बुलाकर अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी। हालांकि बीजेपी ने तुरंत नुपुर शर्मा को बर्खास्त कर दिया था। इसके बाद आठ पूर्व भारतीय नौसैनिकों की मौत की सज़ा को भारत क़तर रिश्तों को दूसरी बड़ी चुनौती माना जा रहा था. क़तर ने इस सज़ा को भी घटा दिया है। क़तर में लगभग आठ-नौ लाख भारतीय काम करते हैं, वहीं दूसरी ओर क़तर भारत को गैस निर्यात करता है. इस लिहाज़ से दोनों देशों के संबंध काफ़ी अहम और मज़बूत भी हैं।

खाड़ी के देशों को लेकर मोदी सरकार की नीति

नरेंद्र मोदी पिछले आठ सालों से भारत के प्रधानमंत्री हैं और इस दौरान उन्होंने खाड़ी के इस्लामिक देशों से संबंधों को मज़बूत करने को काफ़ी गंभीरता से लिया है। पिछले आठ सालों में पीएम मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई का चार बार दौरा किया. पहला दौरा अगस्त 2015 में, दूसरा फ़रवरी 2018 में और तीसरा अगस्त 2019 में। पीएम मोदी ने चौथा दौरा जून 2022 में किया। जब मोदी ने अगस्त 2015 में यूएई का दौरा किया तो वह पिछले 34 सालों में किसी पहले भारतीय प्रधानमंत्री का दौरा था. मोदी से पहले 1981 में इंदिरा गांधी ने यूएई का दौरा किया था।

पिछले साल 28 जून को पीएम मोदी ने जब अबूधाबी एयरपोर्ट पर लैंड किया तो यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन ज़ाएद अल नाह्यान अगवानी में पहले से ही खड़े थे। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन ज़ाएद अल नाह्यान का पीएम मोदी के स्वागत में एयरपोर्ट पर खड़ा रहना प्रोटोकॉल के खिलाफ़ था और उन्होंने इसे भारतीय प्रधानमंत्री के लिए तोड़ा था। पाकिस्तान में मोदी के इस स्वागत की चर्चा काफ़ी हुई थी। भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त रहे अब्दुल बासित ने कहा था कि मई में पाकिस्तानी पीएम शहबाज़ शरीफ़ यूएई गए थे और एक जूनियर मंत्री ने उनकी अगवानी की थी।अब्दुल बासित ने कहा था कि भारत की यह प्रतिष्ठा परेशान करती है।

कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी ने शेख मोहम्मद बिन ज़ाएद अल नाह्यान से अप्रत्याशित दोस्ती बनाई है। 2017 में गणतंत्र दिवस के मौक़े पर मोदी सरकार ने मोहम्मद बिन ज़ाएद अल नाह्यान को ही चीफ़ गेस्ट के रूप में न्योता दिया था। तब मोहम्मद बिन ज़ाएद अल नाह्यान यूएई के राष्ट्रपति नहीं थे बल्कि अबूधाबी के क्राउन प्रिंस थे। परंपरा के हिसाब से भारत गणतंत्र दिवस पर किसी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को ही मुख्य अतिथि बनाता था। लेकिन अल नाह्यान 2017 में गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बनकर आए थे। थिंक टैंक कार्नेगी एन्डाउन्मेंट से अबूधाबी में पश्चिम के एक पूर्व राजदूत ने कहा था कि मोदी की व्यावहारिक राजनीति वाला माइंडसेट और एक मज़बूत नेता वाली शैली सऊदी और यूएई के दोनों प्रिंस पसंद करते हैं। पीएम मोदी ने 2016 और 2019 में सऊदी अरब का दौरा किया था. 2019 में बहरीन और 2018 में ओमान, जॉर्डन, फ़लस्तीनी क्षेत्र का और 2016 में क़तर का दौरा किया था।

पीएम मोदी 2015 में शेख ज़ाएद ग्रैंड मस्जिद और 2018 में ओमान की सुल्तान क़बूस ग्रैंड मस्जिद भी गए थे. नरेंद्र मोदी को सऊदी अरब, यूएई और बहरीन ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी नवाज़ा था। थिंक टैंक कार्नेगी एन्डाउन्मेंट ने अगस्त 2019 की अपनी एक रिपोर्ट में लिखा था, ''शुरुआत में ऐसा लगा था कि नरेंद्र मोदी की राजनीतिक पृष्ठभूमि अरब प्रायद्वीप से संबंधों को आगे बढ़ाने में आड़े आएगी. मोदी हिन्दू राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक हैं।

गंभीर से गंभीर समस्याओं के लिए इन मंत्रों का करें जप, हर तरह के कष्ट होंगे पलभर में दूर

अक्षर से शब्द बनता है, शब्द से मंत्र बनता है। मन्त्र में या मन्त्र से या मन्त्र के द्वारा एक शक्ति जागृत होती है। सृष्टि के प्रारंभ में शिवजी ने जो नृत्य किया, उस नृत्य से चौदह प्रकार की ध्वनियां प्रवाहित हुईं और इन ध्वनियों को ही मंत्रों का मूल आधार माना जाता है। मंत्र ईश्वरीय शक्ति है, जिसके द्वारा मनुष्य की गुप्त शक्तियों का उदय होता है और जिसके नियमित स्मरण एवं चिंतन करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जीवन में सभी के साथ अनेक प्रकार की समस्याएं साथ-साथ चलती हैं। यह समस्याएं कभी-कभी व्यक्ति को अत्यधिक परेशान कर डालती हैं। विवाह में विलम्ब हो, कार्य में सफलता नहीं मिल रही हो, अथवा बीमारियों से परेशान हों तो दवा के साथ सबसे सरल एवं व्ययशून्य उपाय है, मंत्रों का जप।

डॉ. संतोष वाधवानी
रत्न एवं वास्तु विशेषज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष एवं वास्तु एसोसिएशन प्रदेश प्रवक्ता

मंगलदायक विवाह के लिए

विवाह को लेकर चिन्तित युवतियों को मां कात्यायनी की आराधना मनचाहा जीवनसाथी प्राप्त करने के लिए करनी चाहिए, वहीं अपने सपनों की रानी ढूंढ़ने वाले युवकों को मनोवांछित पत्नी प्राप्ति के लिए दुर्गा सप्तशती में वर्णित मंत्र का जप करना चाहिए।

कन्या के विवाह हेतु मंत्रः कात्यायनि महामाये महायोगिन्यधीश्वरि। नन्दगोप सुतं देवि पतिं मे कुरु ते नमः।।

युवक के विवाह हेतु मंत्रः पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीम्। तारिणीं दुर्गसंसारसागरस्य कुलोद्भवाम्।।

रोग नाश के लिए

बीमारी के कारण अगर किसी व्यक्ति के लिए बिस्तर उसका साथी और दवाइयां उसका भोजन बन जाती हैं, तो ऐसे में रोग मुक्ति हेतु नीचे वर्णित रोग नाशक एवं आरोग्य प्राप्ति दोनों मंत्रों का जप विशेष लाभदायक रहता है।

रोगानशेषानपहंसि तुष्टा, रूष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान्।
त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां, त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति।।

आरोग्य और सौभाग्य प्राप्ति के लिए -
देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि में परमं सुखम् ।
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि।।

राम कृपा प्राप्ति एवं जीवन में हर क्षेत्र में सफलता के लिए

किसी भी प्रकार का भय, अपमान से मुक्त होकर राम कृपा प्राप्ति के लिए इस अमोघ मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। इस मंत्र को अपनाने से मनुष्य को अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता हासिल होती है।

राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। सहस्त्रनाम ततुल्यं रामनाम वरानने।।

विविध उपद्रवों से बचने के लिए

सुरक्षा एवं हर प्रकार के उपद्रव, अनिष्ट से बचने के लिए दुर्गा सप्तशती इस सिद्ध मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए।

रक्षांसि यत्रोग्रविषाश्च नागा, यत्रारयो दस्यु बलानि यत्र।
दावानलो यत्र तथाब्धिमध्ये, तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वम्।।

शनि से अप्रभावित रहने के लिए श्री हनुमान जी की उपासना बेहद प्रभावकारी मानी गई है और हनुमानजी की आराधना में सुंदरकांड के पाठ का विशेष महत्व है, अतः अगर सुंदरकांड का पाठ किया जाए, तो हनुमत कृपा से अमंगलों का नाश होकर वर्ष मंगलमय बनेगा। सुंदरकांड के अंतिम दोहे में वर्णित भी है,

'सकल सुमंगल दायक, रघुनायक गुन गान।
सादर सुनहिं ते तरहिं भव, सिंधु बिना जलजान।।'

तुलसीकृत रामायण के सुंदरकांड का पाठ प्रतिदिन करने से रोगों से लड़ने की शक्ति मिलती है। कोर्ट-कचहरी, मुकदमे आदि में विजय प्राप्त होती है, भूत-प्रेत बाधा से छुटकारा मिलता है, ग्रहों की बाधा हो या फिर शनि की साढ़ेसाती या ढैय्या, सुन्दरकाण्ड का पाठ विशेष फायदेमंद रहता है।

बाधा मुक्त होकर धन, पुत्रादि की प्राप्ति के लिए:
सर्वाबाधा-विनिर्मुक्तो धन-धान्य-सुतान्वितः।
मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः।।

विपत्ति नाश के लिए:

शरणागत - दीनार्त - परित्राण -परायणे।
सर्वस्यार्तिहरे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते।।

मौनी अमावस्या पर राशि अनुसार दान करने से होंगी मनोकामना पूरी

डॉ. आर.डी. आचार्य
9009369396
ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ इंदौर (म.प्र.)

9 फरवरी दिन शुक्रवार को मौनी अमावस्या का पर्व मनाया जाएगा। माघ मास की अमावस्या का विशेष महत्व है, इस दिन दान पुण्य और पवित्र नदियों में स्नान करने के सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। मौनी अमावस्या पर अगर राशि अनुसार दान किया जाए तो जीवन के हर कष्ट दूर हो जाते हैं। माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि मौनी अमावस्या कहलाती है। इस बार यह शुभ तिथि 9 फरवरी दिन शुक्रवार को है। मौनी अमावस्या, माघ के महीने का सबसे बड़ा स्नान पर्व है, मौनी अमावस्या का स्नान अन्य सभी स्नान पर्वों में सर्वोत्तम कहा गया है। मौनी अमावस्या के विशेष पुण्यकाल पर स्वयं का उद्धार तथा पितरों को तारने के लिए दान, पुण्य, स्नान का विशेष विधान शास्त्रों में वर्णित है। मौनी अमावस्या पर्व पर दान करने से अनिष्ट ग्रहों की पीड़ा का शमन होता है जिससे वर्ष भर सुख-समृद्धि घर में निवास करती है। धर्मशास्त्र में प्राप्त वर्णन के अनुसार इस दिन दान करने से सब प्रकार के पापों का क्षय, सब प्रकार की आधियों, व्याधियों का निवारण होता है। राशि के अनुसार वस्तुओं का दान करने से जीवन में ग्रह बल प्राप्त होता है।

मेष तथा वृश्चिक राशि

मेष तथा वृश्चिक राशि वाले मौनी अमावस्या के दिन लाल मसूर की दाल, गुण, लाल चंदन, लाल फूल, सिंदूर, तांबा, मूंगा, लाल वस्त्र आदि दान हेतु सम्मिलित करें तो उनको विशेष लाभ प्राप्त होगा।

वृष तथा तुला राशि

वृष तथा तुला राशि वाले मौनी अमावस्या के दिन सफेद वस्त्र, कपूर, खुशबूदार अगरबत्ती, धूप, इत्र आदि, दही, चावल, चीनी, दूध, चांदी, आदि दान हेतु सम्मिलित करें तो उनको विशेष लाभ प्राप्त होगा।

मिथुन तथा कन्या राशि

मिथुन तथा कन्या राशि वाले मौनी अमावस्या के दिन हरी सब्जी, हरा फल, हरा वस्त्र, कांसे का बर्तन, पन्ना या उसका उपरत्न ऑनेक्स, हरी दाल, आदि दान हेतु सम्मिलित करें तो विशेष शुभ फल प्राप्त होगा।

कर्क राशि

कर्क राशि वाले मौनी अमावस्या के दिन दूध, दही, चावल, सफेद वस्त्र, चीनी, चांदी, मोती, शंख, कपूर, बड़ा बताशा आदि का दान अवश्य करें।

कौड़ियों में होता है देवी लक्ष्मी का वास इन स्थानों पर रखने से घर में आएंगी खुशियां

हिंदू धर्म में देवी लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है और हिंदू ज्योतिष शास्त्र में लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए कई उपाय बताए गए हैं। पौराणिक मान्यता है कि कौड़ियों में देवी लक्ष्मी का वास होता है और इसलिए लोग कौड़ियों को घर में रखना शुभ मानते हैं। पंडित आशीष शर्मा यहां कौड़ियों को घर में रखने फायदों और नियमों के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं।

समुद्री जीव से मिलती है कौड़ी

कौड़ियां समुद्र से प्राप्त होती है और देवी लक्ष्मी भी समुद्र मंथन के दौरान समुद्र से ही उत्पन्न हुई थी। यही कारण है कौड़ियों का संबंध देवी लक्ष्मी से बताया गया है। कौड़ियों को शुभता का प्रतीक भी माना जाता है। कौड़ी का आकार चंद्रमा के समान होता है, जो शुभता और समृद्धि का प्रतीक है।

पूजा में जरूर रखें कौड़ियों

यदि आप भी घर में खुशियां लाना चाहते हैं तो पूजा के दौरान कौड़ियों को जरूर रखना चाहिए। पंडित आशीष शर्मा के मुताबिक मां लक्ष्मी की पूजा में कौड़ी चढ़ाना शुभ माना जाता है। पूजा के दौरान 11 कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर मंदिर में दान करने से देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है।

तिजोरी में रखें कौड़ियां

तिजोरी या धन रखने के स्थान पर 9 कौड़ियां लाल कपड़े में बांधकर रखना शुभ होता है। ऐसा करने से धन में वृद्धि होती है और परिवार में समृद्धि आती है। परिवार में कभी भी आर्थिक तंगी नहीं आती है।

मुख्य द्वार पर लगाएं कौड़ियां

पंडित राजेश वैष्णव के मुताबिक, घर के मुख्य द्वार पर 7 कौड़ियां लाल कपड़े में बांधकर लटकाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है। घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है।

पं. राजेश वैष्णव
शनि उपासक ज्योतिष रत्न एवं वास्तु विशेषज्ञ
98272 88490

हवन में नारियल जलाने से होगें कई लाभ

आचार्य पं. संजय वर्मा
9826380407
ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु विशेषज्ञ, इंदौर (म.प्र.)

हिंदू धर्म में पूजा करते समय नारियल का होना बहुत जरूरी होता है। बिना इसके पूजा को अधूरी मानी जाती है। हर शुभ काम की शुरुआत के लिए नारियल का उपयोग किया जाता है। आप अगर नई बाइक लेकर आते हैं, तो नारियल फोड़ते हैं। शादी और गृह प्रवेश में भी इसका उपयोग होता है। हवन के दौरान भी नारियल को भी जलाया जाता है। इस लेख में ज्योतिषाचार्य पंडित अरविंद त्रिपाठी ने विस्तार से बताया है कि हवन में नारियल क्यों जलाते हैं।

सुख-संपन्नता के लिए जलाते हैं नारियल

हवन के दौरान नारियल को जलाने से घर में सकारात्मकता आती है। आपके घर में सुख-समृद्धि का वास होता है। परिवार में वाद-विवाद है, अशांति रहती है, तो हवन में नारियल जला सकते हैं। ऐसा करने से परिवार में सब ठीक होने लगता है।

भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को नारियल है प्रिय

भगवान श्री हरि विष्णु (भगवान विष्णु मंत्र) और माता लक्ष्मी को नारियल से विशेष लगाव है। हवन के दौरान नारियल को जलाने से उनका आशीर्वाद मिलता है। यह आपके जीवन में परेशानियों को दूर करता है।

मनोकामना पूर्ति के लिए जलाते हैं नारियल

आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिल रही है। आप हवन के दौरान नारियल को जलाएं व सभी देवी-देवताओं का ध्यान करें। यह आपकी मनोकामनाओं को पूरा करने में मदद करेगा। हवन करने से आपके घर में देवी-देवता आते हैं, जिससे परिवार में सुख-शांति बढ़ती है।

सस्ती हो गई आम लोगों के भोजन की थाली

प्याज और टमाटर के दाम से जनवरी में मिली राहत

नई दिल्ली। एजेंसी

रिजर्व बैंक की ब्याज दरों को लेकर चल रही अहम बैठक के बीच महंगाई के मोर्चे पर एक अच्छी खबर सामने आई है। एक रिपोर्ट बताती है कि जनवरी महीने के दौरान महंगाई खासकर खाने-पीने की चीजों की महंगाई में कमी आई है, जिसके चलते आम लोगों के भोजन की थाली सस्ती हो गई है।

इतनी रह गई वेज थाली की कीमत

क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने यह रिपोर्ट बुधवार को जारी की। रिपोर्ट के अनुसार, जनवरी में आम लोगों की वेज यानी शाकाहारी थाली की कीमत कम होकर 28 रुपये पर आ गई। एक महीने पहले यानी दिसंबर 2023 में वेज थाली की कीमत 29.7 रुपये थी। हालांकि साल भर पहले की तुलना में दाम अभी भी ज्यादा है. साल भर पहले यानी जनवरी 2023 में वेज थाली की कीमत 26.6 रुपये थी।

रिजर्व बैंक की अहम बैठक जारी

क्रिसिल की यह रिपोर्ट ऐसे समय आई है, जब ब्याज दरों पर निर्णय लेने के लिए रिजर्व बैंक की नीतिगत बैठक चल रही है। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति साल 2024 की पहली और वित्त वर्ष 2023-24 की आखिरी नीतिगत बैठक कर रही है। यह बैठक 6 फरवरी को शुरू हुई है और इसके नतीजे 8 फरवरी को सामने आने वाले हैं. ब्याज दरों पर सेंट्रल बैंक का निर्णय महंगाई खासकर खुदरा महंगाई का ध्यान में रखते हुए लिया जाता है।

प्याज और टमाटर में नरमी

क्रिसिल का कहना है कि जनवरी महीने के दौरान आम लोगों के भोजन की थाली के भाव कम होने का मुख्य कारण प्याज और टमाटर का सस्ता होना है। रिपोर्ट के अनुसार, जनवरी महीने में प्याज की कीमतें महीने भर पहले की तुलना में 26 फीसदी कम हुई हैं।वहीं टमाटर के भाव में इस दौरान 16 फीसदी की गिरावट आई है. प्याज को निर्यात की पाबंदियों के चलते घरेलू बाजार में आपूर्ति सुधरने से राहत मिल रही है, जबकि उत्तरी व पूर्वी राज्यों से नई आपूर्ति आने से टमाटर के भाव में नरमी आई है।

साल भर पहले की तुलना में बढ़े भाव

सालाना आधार पर देखें तो वेज थाली की कीमतें ज्यादा रहने का कारण प्याज और टमाटर के अलावा दाल और चावल भी हैं। क्रिसिल के अनुसार, साल भर पहले यानी जनवरी 2023 की तुलना में प्याज जनवरी 2024 में 35 फीसदी महंगा रहा है, जबकि टमाटर के भाव सालाना आधार पर 20 फीसदी ज्यादा रहे हैं।जनवरी 2023 की तुलना में जनवरी 2024 में दाल और चावल के दाम भी अधिक रहे हैं. यही कारण है कि पिछले महीने सालाना आधार पर वेज थाली के दाम बढ़े हैं।

इतनी सस्ती हुई मांसाहारी थाली

नॉनवेज थाली यानी मांसाहारी थाली के भाव मासिक और सालाना दोनों आधार पर कम हुए हैं। इस साल जनवरी में मांसाहारी थाली की औसत कीमतें 52 रुपये रही हैं। इससे एक महीने पहले यानी दिसंबर 2023 में कीमतें 56.4 रुपये रही थीं, जबकि साल भर पहले यानी जनवरी 2023 में भाव 59.9 रुपये रहे थे।

छोटे व्यापारियों को ग्लोबल पहचान दिला रहा इंडिया शॉपिंग

लोकल ब्रांड्स बिना कमीशन के अमेरिका भेज सकते हैं अपना सामान

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

अपने ब्रांड्स को ग्लोबल पहचान दिलाने के लिए मेहनत कर रहे छोटे व्यापारियों को इंडिया शॉपिंग शानदार सौगात दे रहा है। अमेरिका में घर बैठे लोगों को इंडिया शॉपिंग सेंव - नमकीन, मिठाइयों, मसालों, कपड़े, हैंडीक्राफ्ट, बड़ी – पापड़, कपड़े, कॉस्मेटिक्स जैसी जरूरत की चीजें मनपसंद दुकान से सीधे उपलब्ध करवा रहा है। यह देश भर के छोटे बड़े ब्रांड्स के लिए एक बेहद ख़ास मौका है जहाँ वे अपने उत्पाद को किसी भी प्रकार का कमीशन या सर्विस फीस और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लायसेंस लेने की झंझट के बिना दुनिया भर में भेज सकते हैं।

युवा उद्यमी राहुल भट्ट ने अपनी इंदौर में पत्रकारों से बात करते हुए कहा, 'मैं मध्यप्रदेश के छोटे से शहर जावरा से निकलकर अमेरिका जाकर बसा हूँ। इंडिया शॉपिंग की शुरुआत 10 महीने पहले एक स्टार्टअप के रूप में की थी, लेकिन आज लोग इसे काफी पसंद कर रहे हैं। इंडिया शॉपिंग का मिशन अमेरिका में रहने वाले भारतीयों के लिए एक भरोसेमंद और समर्पित सहायता उपलब्ध कराना है। हमारा लक्ष्य विदेश में रहने वाले एनआरआई का सहायक बनना है ताकि उन्हें देश से दूर रहकर भी देश में मिलने वाला हर सामन उपलब्ध हो सके। हमने खाने - पीने के सामान इंदौर से उपलब्ध करवाकर अपनी सेवाएँ शुरू की हैं। आने वाले दिनों में हम, अमेरिका में रहने वाले भारतीयों के परिवार विशेषकर बुजुर्गों की देखभाल, रियल एस्टेट में निवेश, स्टार्टअप उद्यमों और स्टॉक में लेनदेन की सुविधा, व्यवसाय स्थापित करने में सहायता और यात्रा की व्यवस्था करने की भी योजना बना रहे हैं। इस पूरे सिस्टम की खासियत यह है कि इसमें किसी भी व्यवसायी दुकानदार को किसी भी प्रकार का कमीशन या सर्विस फीस नहीं देनी होती है। ऐसा करने से हम अपने रिटेल पार्टनर्स और ब्रांड्स को अधिक लाभ पहुंचाते हैं, जिससे वे या तो अपने ग्राहकों को फायदा पहुंचा सकते हैं या बेहतर सेवाएं दे सकते हैं।'

चीन और पाकिस्तान में अंदर तक तबाही मचा सकती है ब्रह्मोस मिसाइल

900 किमी पहुंच गई मारक क्षमता

नई दिल्ली। एजेंसी

भारत की ब्रह्मोस मिसाइल से चीन और पाकिस्तान हमेशा से ही खौफ खाते रहे हैं। इसी बीच भारतीय नौसेना ने हाल के समय में ब्रह्मोस मिसाइल की मारक क्षमता को और बढ़ाया ह और एक्सटेंडेड रेंज ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इस सफल परीक्षण के साथ ही ब्रह्मोस मिसाइल की मारक क्षमता बढ़कर अब 900 किलोमीटर तक पहुंच गई है। बड़ी बात यह है कि इस अपग्रेडेशन को पहले से मौजूद ब्रह्मोस मिसाइल के जखीरे पर भी लागू किया जा सकता है। इससे चीन और पाकिस्तान की टेंशन बढ़ सकती है।

भारतीय नौसेना ने 24 जनवरी को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से जमीन पर मौजूद एक लक्ष्य को सफलतापूर्वक मार गिराया था। भारत ने इस मिसाइल परीक्षण के लिए जो एरिया वॉर्निंग (ञ्ऊँश) जारी किया था, उसकी लंबाई करीब 900 किलोमीटर थी। यह ब्रह्मोस मिसाइल के परीक्षण के लिए सबसे लंबी ज्ञात एरिया वॉर्निंग है। इससे यह संकेत मिला है कि ब्रह्मोस मिसाइल अब 900 किमी तक की दूरी तक पहुंचने में सक्षम है।

भारत और रूस की संयुक्त परियोजना है ब्रह्मोस

ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण भारत और रूस के बीच एक संयुक्त परियोजना के जरिए किया गया है। शुरू में इस मिसाइल की रेंज सिर्फ 290 किलोमीटर तक ही सीमित थी। क्योंकि तब भारत मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (श्ऊँ) का भागीदार नहीं था। भारत 2016 में सदस्य बना और मार्च 2017 तक मिसाइल की 400 किमी से अधिक की मारक क्षमता का प्रदर्शन किया। फिर इसकी रेंज को और बढ़ाया गया। इसे फाइटर जेट में भी तैनात किया जा सकता है।

पाकिस्तान के ये इलाके भी आए ब्रह्मोस की जद में

ब्रह्मोस एयरोस्पेस ने खुद बताया था कि वह ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज को 900 किलोमीटर तक करने पर काम कर रहा है। 2016 के बाद से रेंज में तीन गुना वृद्धि इसलिए भी उल्लेखनीय है, क्योंकि इस विस्तार को ब्रह्मोस मिसाइल के सभी वेरिएंट पर लागू किया जा सकेगा। ब्रह्मोस मिसाइल का नया वेरिएंट पूरा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, सियालकोट, लाहौर, गुजरांवाला, कसूर, बहावलनगर, रहीम यार खान जैसे जगहों पर मिलिट्री ठिकानों को आसानी से निशाना बना सकता है।

चीन के ये इलाके भी होंगे जद में

इसके अलावा चीन के कब्जे वाले अक्साई चिन में मौजूद चीनी सेना के ठिकाने भी इसके जद में होंगे। ब्रह्मोस का एक्सटेंडेड वेरिएंट अरुणाचल प्रदेश की सीमा से सटे न्यांगची, सिक्किम से सटे कम्बा काउंटी, उत्तराखंड से सटे गीरंग काउंटी के आसपास स्थित चीनी सेना के ठिकानों और भारतीय सीमा के करीब से गुजरने वाले जी219 हाइवे को भी निशाना बना सकता है।

भारतीय टूरिस्टों के लिए ईरान ने फ्री किया वीजा

नई दिल्ली। एजेंसी

ईरान ने मंगलवार को पर्यटन के लिए विमान से वहां आने वाले भारतीयों के लिए अधिकतम 15 दिन के वीजा फ्री एंट्री प्रोग्राम का ऐलान किया है। ईरानी दूतावास ने कहा कि भारतीय नागरिकों के लिए 4 फरवरी से चार शर्तों के तहत वीजा-मुक्त प्रवेश सुविधा शुरू कर दी गई है। ईरान ने इससे पहले दिसंबर में भारत, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, जापान, सिंगापुर और मलेशिया समेत 32 अन्य देशों के लिए एक नए वीजा-मुक्त कार्यक्रम को मंजूरी दी। ईरान की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि साधारण पासपोर्ट धारक व्यक्तियों को हर छह महीने में एक बार बिना वीजा के अधिकतम 15 दिन के लिए देश में ठहरने की अनुमति दी जाएगी।

4 फरवरी से भारतीय टूरिस्टों को नहीं होगी वीजा की जरूरत

ईरान दूतावास द्वारा मंगलवार को जारी एक बयान के अनुसार, 4 फरवरी से लागू होने वाली नई नीति के साथ भारतीय पर्यटकों को ईरान जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं है। दूतावास ने एक बयान में कहा, 'सामान्य पासपोर्ट रखने वाले व्यक्तियों को हर छह महीने में एक बार बिना वीजा के ईरान में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी, जिसमें अधिकतम 15 दिन का प्रवास होगा.' बयान में साफ किया गया कि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि 15 दिन की अवधि नहीं बढ़ाई जा सकती।

भारत में 'मेड इन इंडिया' गैलेक्सी ए24 सीरीज की बिक्री शुरू

गुरुग्राम। आईपीटी नेटवर्क

सैमसंग की हाल ही में लॉन्च की गई फ्लैगशिप गैलेक्सी ए24 सीरीज की भारत में बिक्री शुरू हो जाएगी। 'मेड इन इंडिया' गैलेक्सी ए24 अल्ट्रा, गैलेक्सी ए24+ और गैलेक्सी ए24 स्मार्टफोन लाइव ट्रांसलेट, इंटरप्रेटर, चैट असिस्ट, नोट असिस्ट और ट्रांसक्रिप्ट असिस्ट जैसी सुविधाओं से लैस है। सैमसंग कीबोर्ड में निर्मित एआई हिंदी सहित 13 भाषाओं में रियल टाइम में मैसेज का अनुवाद करने में सक्षम है। कार में, एंड्रॉएड ऑटो अपने आप आने वाले मैसेज का सारांश सामने रखते हुए प्रासंगिक रिप्लाई और एक्शन का भी सुझाव देगा।

गैलेक्सी ए24 सीरीज का निर्माण भारत में सैमसंग की नोएडा स्थित फैक्ट्री में किया जा रहा है। सैमसंग को अपने इस गैलेक्सी ए24 सीरीज के लिए रिकॉर्ड प्री-बुकिंग मिली हैं, जिससे यह भारत में अब तक की सबसे सफल एस सीरीज बन गई है। गैलेक्सी ए24 सीरीज गूगल के साथ सहज, जेस्चर संचालित 'सर्कल टू सर्च' की शुरुआत करने वाले पहला फोन है, जो सर्च के मामले में अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है। उपयोगी, उच्च-गुणवत्ता वाले सर्च रिजल्ट देखने के लिए यूजर गैलेक्सी ए24 की स्क्रीन पर सर्कल बना सकते हैं, हाइलाइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं या फिर टैप कर सकते हैं। कुछ चुनिंदा सर्च के लिए, जेनेरिक एआई-संचालित ओवरव्यू पूरे वेब से हासिल जानकारी और संदर्भ मुहैया कराता है। गैलेक्सी ए24 सीरीज़ का प्रोविजुअल इंजन एआई-संचालित टूल की एक व्यापक श्रृंखला है, जो इमेज कैप्चरिंग क्षमताओं को नई ऊंचाई पर ले जाते हुए रचनात्मक स्वतंत्रता को ऑप्टिमाइज करता है। गैलेक्सी ए24 अल्ट्रा पर क्वाड टेली सिस्टम अब एक नए 5 ऑप्टिकल ज़ूम लेंस के साथ आता है जो एडैप्टिव पिक्सल सेंसर की बदौलत 2x, 3x, 5x से 10x तक ज़ूम स्तरों पर ऑप्टिकल-गुणवत्ता प्रदर्शन को सक्षम करने के लिए 50MP सेंसर के साथ काम करता है। इमेजेज बेहतर डिजिटल ज़ूम के साथ 100x पर बिल्कुल स्पष्ट नजर आती हैं। एडवांस्ड नाइटोग्राफी क्षमताओं के साथ, गैलेक्सी ए24 स्पेस ज़ूम पर शूट की गई तस्वीरें और वीडियो किसी भी स्थिति में शानदार होते हैं। गैलेक्सी ए24 अल्ट्रा का बड़ा पिक्सल आकार, जो अब 1.4 माइक्रोमीटर है, 60% बड़ा है, जो धुंधली स्थिति में अधिक रोशनी कैप्चर करने में मदद करता है। व्यापक ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजर (ओआईएस) कोण और बेहतर हैंड-शेक मुआवजा धुंधलापन को कम करने में मदद करता है। फ्रंट और रियर दोनों कैमरे शोर को कम करने के लिए समर्पित आईएसपी ब्लॉक से लैस हैं।

टाटा मोटर्स ने पेश किया टर्बोट्रॉन 2.0 इंजन, जो ट्रकिंग को बनाता है अधिक कुशल और विश्वसनीय

मुंबई। आईपीटी नेटवर्क

भारत की सबसे बड़ी वाणिज्यिक वाहन बनाने वाली कंपनी, टाटा मोटर्स ने आज अपना तकनीकी रूप से उन्नत इंजन, टर्बोट्रॉन 2.0 पेश किया है। ट्रकिंग में उत्कृष्टता का एक नया मानक स्थापित करेगा। यह अत्यधिक ईंधन कुशल और विश्वसनीय इंजन है। इस बहुपयोगी इंजन को पूरी तरह से देश में ही बनाया गया है, और यह सभी श्रेणियों में कई प्रयोगों के लिए 19-42 टन रेंज में टाटा ट्रकों को शक्ति प्रदान करेगा। टर्बोट्रॉन 2.0 इंजन तेजी से बढ़ते ई-कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स, पार्सल और कूरियर सेगमेंट के लिए पूरी तरह से उपयुक्त है। इसके ग्राहकों से मिले फीडबैक के आधार पर उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह इंजन बेहतर ड्राइविंग अनुभव प्रदान करता है। साथ ही स्वामित्व की कुल लागत को कम करता है। इस इंजन के मजबूत प्रदर्शन के लिए इंजीनियर किया गया है। (टीसीओ)। इसके अलग-अलग ड्यूटी साइकिल और कठोर इलाकों में 30 लाख किमी से ज्यादा और कुल 70,000 घंटों तक के कठोरता परीक्षण के दौर से गुजारा गया है। टर्बोट्रॉन 2.0 इंजन में बीएस6 स्टेज 2 उत्सर्जन नियमों का पूरी तरह अनुपालन किया गया है। टर्बोट्रॉन 2.0, प्लेटफॉर्म-एग्नोस्टिक है और इसे सिग्ना, अल्ट्रा, एलपीटी और काउल प्लेटफॉर्म के साथ पेश किया गया है। यह 6 साल/6 लाख किमी की वारंटी के साथ आता है।

कुशल और बहुपयोगी 5-लीटर टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन टर्बोट्रॉन 2.0 को 180-204 पीएस तक की कई रेंज में पेश किया गया है। इसकी बेहतर ड्राइविंग के लिए 700-850 एनएम की रेंज में एक फ्लैट टॉर्क कर्व प्रदान करने के लिए इंजीनियर किया गया है। लंबे तेल निकास और 1 लाख किमी के सर्विस इंटरवल की इसकी खासियत उच्च राजस्व जनरेट करने के लिए इसे लंबी अवधि तक काम करने की क्षमता देती है।

टर्बोट्रॉन 2.0 के बारे में बताते हुए टाटा मोटर्स के प्रेसिडेंट और चीफ टेक्नोलॉजी ऑफीसर, श्री राजेंद्र पेटकर ने कहा, 'टर्बोट्रॉन 2.0 हमारे सबसे उन्नत आंतरिक दहन इंजनों में से एक है। नवीनतम तकनीकों के साथ इंजीनियर किया गया, यह ट्रकों को कम समय में लंबी दूरी तय करने में सक्षम बनाता है। इसके मजबूत प्रदर्शन और उच्च ईंधन दक्षता ने भारत में ट्रकिंग के लिए नए उद्योग मानक स्थापित किए हैं।'

टाटा मोटर्स के फ्लीट एज ने 5 लाख कमर्शियल वाहनों को डिजिटल तरीके से जोड़ा

मुंबई। आईपीटी नेटवर्क

भारत में कमर्शियल वाहन बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी, टाटा मोटर्स ने आज अपने डेडिकेटेड कनेक्टेड व्हीकल प्लेटफॉर्म फ्लीट एज के साथ 5 लाख कमर्शियल वाहनों को जोड़ने की घोषणा की है। वाहनों के कुशल प्रबंधन के लिए विशेषतौर पर डिजाइन किया गया, फ्लीट एज स्मार्ट टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर वाहन का अपटाइम बढ़ाता है और सड़क सुरक्षा में सुधार करता है। यह प्लेटफॉर्म इससे जुड़े हर वाहन की स्थिति, सेहत, जगह और ड्राइवर के व्यवहार पर वास्तविक समय में कार्यवाही के योग्य जानकारियाँ साझा करता है। इस प्रकार वाहनों के मालिक एवं प्रबंधक परिचालन क्षमता को बढ़ाने, लॉजिस्टिक्स खर्च कम करने और अपना फायदा बढ़ाने के लिये बेहतर फैसले कर सकते हैं।

अपनी तरह की इस पहली उपलब्धि को हासिल करने के बारे में श्री भारत भूषण, हेड-डिजिटल बिजनेस, टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स ने कहा, 'टाटा मोटर्स लॉजिस्टिक्स को शानदार और सक्षम बनाने के लिये प्रतिबद्ध है। फ्लीट एज अपने महत्वपूर्ण मजबूत प्रस्ताव, डाटा पर आधारित इंटेलिजेंस, रियल-टाइम जानकारियों और वाहन के पूर्वानुमान के साथ इस कोशिश में एक असली गेमचेंजर रहा है। इससे फ्लीट का ज्यादा स्मार्ट प्रबंधन संभव हुआ है। हमारे लाखों ग्राहकों को इसके इस्तेमाल से फायदा हो रहा है। उनकी परिचालन क्षमता बढ़ रही है और ट्रकों के स्वामित्व की कुल लागत कम हो रही है। सच्चे भागीदार के तौर पर हम अपने ग्राहकों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, ताकि उनका बिजनेस ज्यादा सफल हो।''

फ्लीट एज अपने यूजर-फ्रेंडली इंटरफेस के साथ आता है। यह वाहन में पहले से इंस्टॉल किये गये विभिन्न सेंसर्स से मिलने वाले कई इनपुट्स दिखाता है। इस प्रकार वाहन की सेहत पर लगातार नजर रखी जा सकती है और सही समय पर मैंटेनेन्स के लिये अलर्ट्स से वाहन का अपटाइम बढ़ाया जा सकता है। ईंधन की बचत करने वालीं तकनीकें बताने के लिये यह ड्राइविंग के तरीकों का विश्लेषण भी करता है और ड्राइवर के व्यवहार पर नजर रखता है।

देश में बीमा की पहुंच महज 4% लोगों के पास, तब भी इस पर 18% जीएसटी, संसदीय समिति ने कह दी बड़ी बात

नई दिल्ली। एजेंसी

दुनिया भर में इंश्योरेंस बिजनेस के हिसाब से भारत का स्थान 10वां हो गया है। साल 2021 में भारत की बाजार हिस्सेदारी 1.78 से बढ़ कर 1.85 फीसदी हो गई थी। यही नहीं इस साल इंश्योरेंस प्रीमियम में भी 13.46 फीसदी की बढ़ोतरी देखी गई। लेकिन, भारत वैसे चुनिंदा देशों में शामिल है जहां बीमा प्रीमियम पर 18 फीसदी की जीएसटी वसूली जाती है। इस पर संसद की एक कमेटी ने भी ऐतराज जताया है। कमिटी ने कहा है कि इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स पर जीएसटी को तर्कसंगत बनाने की आवश्यकता है।

बीमा का बढ़ रहा है कारोबार

बीमा क्षेत्र के नियामक आईआरडीएआई के एनुअल रिपोर्ट 2021-22 के मुताबिक भारत में बीमा का कारोबार बढ़ रहा है। साल 2020 के दौरान भारत दुनिया भर के इंश्योरेंस बिजनेस में 11वां स्थान रखता था। लेकिन साल 2021 में यह सुधर कर 10वें स्थान पर आ गया। यही नहीं, भारत की बाजार हिस्सेदारी भी साल 2020 में 1.78 के मुकाबले साल 2021 में सुधर कर 1.85 हो गई है। भारत में साल 2021 के दौरान कुल इंश्योरेंस प्रीमियम में 13.46 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। यह भी तब जबकि रीयल ग्रोथ में 7.8 फीसदी इंफ्लेशन को एडजस्ट किया गया। इस साल दुनिया भर में इंश्योरेंस प्रीमियम में 9.04 फीसदी की ही बढ़ोतरी हुई थी।

संसदीय कमिटी ने क्या कहा है?

केंद्र सरकार में वित्त राज्यमंत्री रहे जयंत सिन्हा की अध्यक्षता में संसद में फाइनेंस पर एक स्थाई समिति (Standing Committee on Finance) बनी है। इसी समिति ने सिफारिश की है कि इंश्योरेंस प्रॉडक्ट, विशेष रूप से हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस पर जीएसटी को तर्कसंगत बनाया जाए। कमिटी ने यह भी सुझाव दिया है कि सरकार की तरफ से भारतीय रिजर्व बैंक बीमा इंडस्ट्री की पूंजी जरूरतों को पूरा करने के लिए 'ऑन- टैप बॉन्ड जारी कर सकता है, जो 40- 50,000 करोड़ रुपये पर आंका गया है। कमिटी ने अपनी सिफारिशों में कहा कि यह बात सामने आई है कि हाई जीएसटी रेट के कारण प्रीमियम की रेट ज्यादा हो जाती है।

अभी इंश्योरेंस प्रीमियम पर कितना है जीएसटी

इस समय चाहे लाइफ इंश्योरेंस की बात करें या नॉन लाइफ या जनरल इंश्योरेंस की, सभी के प्रीमियम पर जीएसटी की दर 18% है। तभी तो संसद की स्थायी समिति ने सिफारिश की है कि हेल्थ बीमा प्रॉडक्ट, विशेष रूप से सीनियर सिटोजन के लिए रिटेल पॉलिसियों और माइक्रोइन्श्योरेंस पॉलिसियों (पीएमजेएवाई के तहत तय सीमा तक वर्तमान में 5 लाख रुपये) और टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी पर जीएसटी रेट को कम किया जा सकता है।

भारत में इंश्योरेंस पेनेट्रेशन काफी कम

आईआरडीए की एनुअल रिपोर्ट 2021-22 के मुताबिक भारत में इस समय इंश्योरेंस पेनेट्रेशन यानी बीमा की पहुंच महज चार फीसदी लोगों तक ही है। लाइफ इंश्योरेंस में तो यह तीन फीसदी है जबकि नॉन-लाइफ इंश्योरेंस में तो यह एक फीसदी ही है। इसके उलट ग्लोबल एवरेज सात फीसदी है। भारत में परंपरागत तरीके से लाइफ इंश्योरेंस की भारी भागीदारी रही है। साल 2021 के दौरान में लाइफ इंश्योरेंस की हिस्सेदारी 76 फीसदी थी जबकि दुनिया भर में लाइफ इंश्योरेंस की हिस्सेदारी महज 43.7 फीसदी ही है।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13, प्रेस काम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक- सचिन बंसल

सूचना/चेतावनी- इंडियन प्लास्ट टाइम्स अखबार के पूरे या किसी भी भाग का उपयोग, पुनः प्रकाशन, या व्यावसायिक उपयोग बिना संपादक की अनुमति के करना वर्जित है। अखबार में छपे लेख या विज्ञापन का उद्देश्य सूचना और प्रस्तुतिकरण मात्र है। अखबार किसी भी प्रकार के लेख या विज्ञापन से किसी भी संस्थान की सिफारिश या समर्थन नहीं करता है। पाठक किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्वविवेक से निर्णय करें। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर, मप्र रहेगा।